



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1993/भाद्र 13, 1915

No. 180] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1993/BHADRA 13, 1915

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1993

विषय :— द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत आने वाले देशों को कृत्रिम यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप् की मर्दे निर्यात करने के लिए वर्ष 1994-1996 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्तें ।

सं. 1/4/93-ई पी (टी एण्ड जे) 1—1. प्रस्तावना :— यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप् के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय आर्थिक सहाय, आस्ट्रिया, फिनलैंड तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात तथा आयात नीति (1992-1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के खण्ड 1 के परिशिष्ट 43-जे की मद संख्या 11 में निहित उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए हकदारियों के आबंटन संबंधी नीति (जिसे इसके पश्चात् आबंटन नीति कहा गया है) वह होगी जो इसमें इसके पश्चात् व्योरेवार है ।

2. प्रशासन :— जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऊनी यार्न फैब्रिक्स तथा मेड अप्स, जिनका आबंटन, सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) तथा वर्ग 31 ई ई सी, जिनका आबंटन कार्यकारी निदेशक, सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (एस एण्ड आर टी ई पी सी) द्वारा किया जायगा, को छोड़कर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टेक्सप्रोसिल) के कार्यकारी निदेशक सभी यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड अप्स मर्दों की हकदारी का आबंटन करेंगे । तथापि, ऐसे सभी निर्यातों के लिए प्रमाणीकरण केवल टेक्सप्रोसिल द्वारा ही किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल, सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् तथा कार्यकारी निदेशक, सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का अभिप्राय उनसे तथा शामिल किए गए ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें वो अपने ऐसे कार्य तथा उत्तरदायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें ।

(3) कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल, सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् तथा कार्यकारी निदेशक,

सिधेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आबंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के निर्वाचन के संबंध में अन्तिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अधिकारियों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में समय समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनःआबंटित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को दिया जाएगा जो आयात-निर्यात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हों।

3. आधार अवधि :- इस अधिसूचना में किसी भी स्थान पर आने वाले "आधार अवधि" वाक्यांश का अभिप्राय किसी भी आबंटन वर्ष के लिए उस कलेण्डर वर्ष से होना जो उस आबंटन वर्ष के पूर्व वर्ष से ठीक पहले आया हो।

उदाहरणार्थ, वर्ष 1994 के लिए आधार वर्ष 1992 का वर्ष होगा।

4. आबंटन की प्रणाली :- (1) प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आबंटन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मद के सामने विनिर्दिष्ट करों पर किया जाएगा।

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) किमत निर्यात हकदारी (पी पी ई)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	10
(ख) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एन ई ई)	15
(ग) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर जी ई)	15
(घ) गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (हथकरघा वस्त्रों के लिए एन क्यू ई में से)	10
(ङ) विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी ई ई)	5

योग :

100 प्र. श.

(2) तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका में मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अन्तर्गत हथकरघा मेड अप्स मदें निम्नोक्त अनुसार आबंटित की जायेंगी :

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(10)
(ख) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर जी ई)	35
(ग) गैर-कोटा निर्यातकों की हकदारी (एन क्यू ई)	10
	100 प्र. श.

(3) उपरोक्त के अलावा, अभ्यार्पणों, लोचशीलताओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपबन्ध होगी उसका आबंटन भी तैयार माल निर्यात की प्रणाली के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) मांगपट्टन में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा।

(5) उच्च मूल्य की मदों तथा गैर-कोटा निर्यात प्रणालियों के आबंटन सहित निम्न निर्यात हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान सकल विदेशी मुद्रा क्यूली की संकल्पना को अपनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त अलग से जारी किए जायेंगे।

5. विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) :- सूती यार्न फैब्रिक्स तथा मेड-अप के सम्बन्ध में पी पी ई के परिकलन के लिए अभिकरण कार्यकारी निदेशक टेक्सप्रोसिल होगा। श्रेणी 31 यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंध में सम्बंधित अभिकरण सिधेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् होगा। श्रेणी 31.1 (वरस्टिड फैब्रिक्स) / कनाडा के सम्बन्ध में सम्बंधित अभिकरण सचिव, डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी होगा। परिकलन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :

(1) उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदन कर्तव्यों द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, आबंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त देश/श्रेणी में भारत के वार्षिक औसत निर्यात की सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया जाए

(2) जिन निर्यातकों ने आधार अवधि के दौरान किसी देश/श्रेणी विशेष में विगत निर्यात हकदारी के लिए आवेदन किया है उन सभी निर्यातकों की औसत इकाई मूल्य वसूली का निर्धारण किया जाएगा तथा औसत मूल्य से उच्चतर इकाई मूल्य वसूल करने वाले निर्यातकों को, निर्यात में उनके अंशदान के समानुपात में 10 प्रतिशत आरक्षित पूल (एन बी ई) में से अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया जाएगा।

(3) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान विगत निर्यात हकदारी पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से हस्तांतरणीय होगी। 30 सितम्बर के बाद हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हस्तांतरित विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) को पी पी टी के नाम से जाना जाएगा।

(4) पी पी टी के आधार पर पोत लदानों की गणना हस्तांतरणकर्ता द्वारा किए गए निर्यात के रूप में की जाएगी।

(5) पी पी टी के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

6. विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणाली :—(1) इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन उन विनिर्माता निर्यातकों को किया जायेगा जिन्होंने आधार अवधि के दौरान अपने संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त रूप से प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया है। पात्रता के नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

(2) इस प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातक की पात्रता तथा उत्पादन क्षमता निर्धारित करने का प्राधिकार वस्त्र आयुक्त को होगा।

(3) इस व्यवस्था के अंतर्गत आबंटन केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए होगा, जिनका विनिर्माण वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित आधुनिकीकृत तथा उन्नत उत्पादन एकक में होगा।

(4) उपलब्ध मात्रा, वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित पात्र आवेदकों को उत्पादन क्षमता के आधार पर कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल द्वारा वितरित की जाएगी। उपर्युक्त आबंटन हेतु प्रत्येक पात्र आवेदक अधिक से अधिक सात श्रेणियों को चुन सकता है।

(5) जब किसी भी श्रेणी में किसी आवेदक को आबंटित की गई मात्रा (वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित) बहुत कम होती है, कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल ऐसे तरीके से ऐसी मात्रा का पुनःआबंटन करेगा ताकि प्रत्येक आवेदक को आबंटित की गई मात्रा उचित रूप से पर्याप्त हो।

(6) इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन हस्तांतरणीय नहीं है। आबंटित लदान का प्रमाणीकरण के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि निर्यात की जा रही वस्तुओं का विनिर्माण उन उत्पादन एककों में हुआ है जिनका आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया है।

7. तैयार माल निर्यातक हकदारी प्रणाली (आर जी ई):—

(1) मात्राएं एफ ओ बी मूल्य की 5 प्र.श. की दर पर

ई एम डी / बी जी के प्रति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित की जाएगी।

(2) किसी दिन विशेष को जब उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा आबंटित होती है, पात्रता उस दिन को प्राप्त आवेदन पत्रों के बीच उच्चतर मूल्य आधार पर निश्चित की जाएगी।

(3) वस्त्र आयुक्त यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो तैयार माल निर्यात प्रणाली के अंतर्गत किसी निर्यातक द्वारा एक दिन में प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए लागू होने वाली अधिकतम मात्रा का निर्धारण कर सकता है।

8. गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) प्रणाली :— सूती यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप्स के संबंध में गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) का परिकलन करने का अभिकरण कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल होगा। श्रेणी 3/ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंध में कार्यकारी निदेशक, सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् संबंधित अभिकरण होगा। श्रेणी 31.1 (वरस्टिड फैब्रिक) / कनाडा के संबंध में उन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् संबंधित अभिकरण होगा। परिकलन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :—

(1) गैर-कोटा हकदारियों का वितरण, आधार वर्ष के दौरान गैर-कोटा देशों को यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप्स के निर्यात तथा कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यात पर आधारित होगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त मुद्रा में प्राप्त हो तथा निर्यातक का न्यूनतम निर्यात-निष्पादन आधार अवधि के दौरान 15 लाख र. मूल्य का हो।

(2) इस प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित 10 प्रतिशत हकदारी में से 7 प्रतिशत सभी निर्यातकों के लिए सामान्य होगी तथा 3 प्रतिशत विशुद्ध रूप से ऐसे निर्यात के लिए होगी जो कि केवल हथकरघा फैब्रिक तथा मेड-अप्स के ही हों।

(3) इस प्रणाली के अंतर्गत हकदारी का परिकलन आधार अवधि के दौरान निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा तथा उपलब्ध मात्रा का वितरण विशिष्ट आवेदनकर्ताओं के यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप्स के पृथक रूप से किए गए निर्यात के मूल्य के समानुपात आधार पर किया जाएगा।

(4) एक निर्यातक को आबंटन के लिए सात देशों / श्रेणियों के मिश्रण का विकल्प की अनुमति होगी।

(5) विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) पर लागू होने वाली सभी शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) पर भी लागू होंगी।

(6) गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) हस्तांतरणीय है (जिसे इसके पश्चात् एन क्यू टी के रूप में उल्लिखित किया गया है) तथा इसके अंतरण की शर्तें वही होंगी जोकि पी पी ई के मामले पर लागू होती हैं।

एन क्यू टी अहस्तांतरणीय है।

9. विद्युत्करघा निर्यातक हकदारी (पी ई ई) प्रणाली :— वस्त्र आयुक्त, पी ई ई प्रणाली के अंतर्गत आबंटन की पावता के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मानदण्डों को अलग से अधिसूचित करेंगे।

10. (1) आबंटन के उपयोग के उद्देश्य के लिए विगत निर्यात हकदारी गैर-कोटा निर्यात हकदारी विद्युत्करघा, निर्यात हकदारी तथा विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणालियों के संबंध में एकल अवधि अर्थात् जनवरी-सितम्बर होगी। निर्यातकों को 30 सितम्बर तक अपने समस्त आबंटन का उपयोग कर लेना चाहिए। 30 सितम्बर के बाद अप्रयुक्त मात्राएं, मद पर लागू न्यूनतम निर्यात कीमत की 25 प्रतिशत की दर से वैध करार तथा पेशगी जमा राशि/ बैंक गारंटी पर उसी वर्ष के 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है। वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल के पास हकदारी की मूल वैधता की अवधि के दौरान पहुंच जाना चाहिए।

(2) उपर्युक्त प्रणालियों में उद्दिष्ट की गई मात्राएं कोटा वर्ष की 1 जनवरी को खोली जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्वतन वर्ष के दौरान आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं।

(3) तैयार माल निर्यातक हकदारी प्रणाली के अंतर्गत हकदारियों प्रत्येक वर्ष में पूर्व निर्धारित तारीखों को जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर माह के दौरान चार बार खोली जायेगी। लक्ष्य के 75 प्रतिशत को जनवरी, अप्रैल के दौरान रिलीज किया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को जुलाई और अक्तूबर के दौरान रिलीज किया जायेगा।

(4) यदि पूर्व निर्धारित तारीख के बीच इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन के लिए अतिरिक्त मात्राएं उपलब्ध हो जाती हैं तो संबंधित एजेंसी द्वारा ऐसी मात्राएं, वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन से व्यापार क्षेत्र को 15 दिनों का नोटिस देने के बाद किसी भी समय रिलीज कर दी जायेगी।

11. प्रमाणीकरण की वैधता: तैयार माल निर्यातक प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणीकरण की वैधता 30 दिनों की अवधि के लिए होगी। विगत निर्यातक हकदारी, विनिर्माता निर्यातक हकदारी तथा गैर-कोटा निर्यातक/विद्युत्करघा निर्यातक हकदारी तथा अन्तरित विगत निर्यात तथा गैर-कोटा हकदारियों के अंतर्गत प्रमाणीकरण की वैधता 30 दिनों की अवधि अथवा हकदारी प्रमाणपत्र की समाप्ति तक, इसमें से जो भी पहले हो, तक होगी। वस्त्र आयुक्त यदि इस बात से संतुष्ट हैं कि निर्यातक ऐसी परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका जोकि उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह अत्येक मामले में तीन कार्य दिवसों की अवधि तक वैधता की अवधि को बढ़ाने की संख्यौरी दे सकता है।

12. न्यूनतम निर्यात कीमत (एम ई पी) :— वस्त्र आयुक्त, विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित करेंगे। जोकि सभी प्रणालियों के अंतर्गत मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अधधीन होगी। निम्ननम कीमत निर्धारित करते समय हाल ही के समय में औसत इकाई मूल्य वसूली, वार्षिक, स्तर का उपयोग करने की प्रवृत्तियों तथा विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाएगा।

13. कम कारोबार वाली मदें :— (1) एक मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में अधिसूचित किया जाएगा यदि आधार अवधि के दौरान उसका उपयोग, उक्त वर्ष के आधार स्तर के 75 प्रतिशत से कम रहा हो। कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल पिछले वर्ष के अधिक से अधिक 1 दिसंबर तक उन मदों को अधिसूचित करेगा जो कम कारोबार वाली मदें हैं।

(2) कम कारोबार वाली मदों के लिए इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध में निहित व्यवस्था के बावजूद जहां कहीं भी ई एम डी/बी जी लागू होती है, वहां यह तैयार माल निर्यातक हकदारी प्रणाली के अंतर्गत माल लदान के लिए एफ ओ बी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगी।

तथापि, यह छूट बिना किसी पूर्व सूचना के वापिस ली जा सकती है।

14. पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी (ई एम डी/बी जी) जब्त करना : (1) जो निर्यातक हकदारी को 90 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करता है उसकी ई एम डी/बी जी की पूरी राशि रिलीज कर दी जाएगी।

(2) जैसा कि इसके पश्चात् व्यवस्था है उस निर्यातक की ई एम डी/बी जी जब्त कर ली जाएगी जोकि पी पी टी सहित निर्यात हकदारी के 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है। कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल, अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में यदि उपयोग 75 प्रतिशत तक होता है तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में यदि उपयोग 50 प्रतिशत तक होता है तो उस स्थिति में उपयोग में कभी रहने के समानुपात ई एम डी/बी जी जब्त कर लेगा। यदि उपयोग उपर्युक्त से कम होता है तो ई एम डी/बी जी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

(3) इस प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकलन प्रत्येक अवधि/प्रणाली के आधार पर पृथक रूप से किया जाएगा। वैधता/प्रमाणीकरण की अवधि बढ़ाने के मामले में उस मात्रा के लिए उपयोग के प्रतिशत का पृथक रूप से परिकलन किया जाएगा जिसके प्रमाणीकरण/वैधता की अवधि बढ़ाई गई है।

(4) जब्त की गई ई एम डी/बी जी की समस्त राशि सरकार के पब्लिक डिपॉजिट खाते में जमा कर दी जाएगी जिसका संचालन उसी प्रकार से होगा जैसा कि सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी।

(5) जिन व्यक्तियों को निर्यात हकदारियां आबंटित की जाती हैं यदि ये इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के भविष्य में वे इन हकदारियों के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(6) जल्ती के पूर्व एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(7) यदि एक निर्यातक किसी भी प्रणाली के अंतर्गत वैधता अवधि के दौरान अथवा वैधता की समाप्ति से 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी हकदारियां वापिस लौटा देता है तो उस स्थिति में हकदारी के अंतर्गत शामिल की गई ईएम डी/बैंक गारंटी की 50 प्रतिशत राशि निर्यातक को रिलीज कर दी जाएगी।

15. ईएम डी/बी जी के खिलाफ अपील :—एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 14 के अंतर्गत कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल/सिथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जल्ती के आदेश से हानि पहुंचती है तो वह जल्ती की ऐसी सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा। अपीलों का निपटारते समय वह अपरिहार्य घटना की स्थितियों के अलावा अधिसूचना में परिभाषित जल्ती की शर्तों को भी ध्यान में रखेगा। इस प्रयोजन के लिए वस्त्र आयुक्त से अभिप्राय वस्त्र आयुक्त तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए अन्य अधिकारी से होगा। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह उसे व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह इस आशय के निर्णय की सूचना भेजने से 60 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के खिलाफ अपीली समिति, वस्त्र मंत्रालय के समक्ष अपील कर सकता है।

16. रोकें गए माल की रिलीज करवाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत : (क) जहां आयातक देश द्वारा लदान की गई गैर-कोटा मद अथवा किसी अन्य प्रतिबंधित मद को प्रतिबंधित मद की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो वहां पुनर्वर्गीकृत श्रेणी के लिए ईसी/बीजा, निर्यातक द्वारा पहले आओ पहले पाओ प्रणाली को छोड़कर किसी भी प्रणाली में अवश्य कोटा को वापस किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। यदि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में आबंटन के लिए हकदारियां अधिशेष रहती हैं तो उस स्थिति में निर्यातक द्वारा कोई कोटा वापस किए बिना पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अधिशेष में नाम डाल कर ईसी/बीजा जारी कर दिया जाये। इस पैरा के अनुबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें पोतलदान के लिए खरीददार को बदलने की आवश्यकता हो जोकि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में या 30 सितम्बर

के बाद समय वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य प्रणाली से प्रभावित हुआ हो तथा उन मामलों में जिनमें आयातक देशों में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

(ख) जब प्रतिबंधित श्रेणी की निर्यात के लिए लदान की गई वस्तुओं का उपर्युक्त अनुसार अन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो तब देश से जहाज से भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को वापस की जाए :

(1) निर्यातक उस मूल ई सी/बीजा को वापस कर दे जोकि उसे जारी किया गया था।

(2) हकदारी प्रमाणपत्र, जिसे निर्यात के समय नामे डाला गया था, अनुरोध किए जाने पर संबंधित मात्रा के लिए वैध बना रहेगा।

(ग) उपर्युक्त (क) के मामले में पुनः वर्गीकृत श्रेणी की निम्नतर कीमत वसूल की जाए। तथापि, उपर्युक्त मामलों में वस्त्र आयुक्त इस शर्त में ढील दे सकता है।

(घ) जहां निर्यातक को पुनः वर्गीकृत श्रेणियों के लिए कोटा वापस करना अपेक्षित होता है, ऐसे मामलों में उसे पी पी ई, एन क्यू ई या एम ई ई में अपनी हकदारियों अथवा हस्तांतरण से प्राप्त की गई हकदारियों में से भी ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मामले का निपटारा 1 अक्टूबर के बाद किया जाना है तथा अन्तरण करने की अनुमति नहीं है तथा वापस करने के लिए निर्यातक के पास अपनी निजी हकदारियां नहीं हैं तो उस स्थिति में वह इस आशय का परिवचन प्रस्तुत करेगा कि वह उत्तरवर्ती वर्ष की हकदारी से (निजी या हस्तांतरित) 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा को वापस कर देगा। ऐसे परिवचन पत्र के साथ निम्नतर कीमत मूल्य पर परिकलित की गई मात्रा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि को पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में उत्तरवर्ती वर्ष के लिए निर्यातक को किसी भी देश/श्रेणी में पीपी, एन क्यू, एम ई हकदारियों का आबंटन अपेक्षित मात्रा वापस करने के बाद ही किया जाए। यदि मात्रा वापस नहीं की जाती है तो पेशगी जमा राशि बैंक गारंटी जप्त कर ली जाये।

17. निर्यातकों द्वारा कोटा संबंधी अनाचार से निपटने की प्रक्रिया: (1) जो निर्यातक कोटा प्राप्त करने, कोटा का उपयोग करने या कोटा के उपयोग को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की बेईमानी करने में लिप्त पाये जाते हैं, उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये जाएं।

(2) ऐसे मामलों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा —

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. वस्त्र आयुक्त                    | —अध्यक्ष    |
| 2. अध्यक्ष, टेक्सप्रोसिल            | —सदस्य      |
| 3. उपाध्यक्ष/उपसभापति, टेक्सप्रोसिल | —सदस्य      |
| 4. कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल   | —सदस्य      |
| 5. सचिव, टेक्सप्रोसिल               | —सदस्य-सचिव |

यदि समिति श्रेणी 3 (ई ई सी)/श्रेणी 31क (कनाडा) के निर्यात में अनाचार से संबंधित मामलों पर विचार करती है तो अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, एस आर टी ई पी सी/अध्यक्ष तथा सचिव, डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी से अनुरोध किया जाएगा कि वे विशेष प्रतिष्ठियों के रूप में समिति की बैठक में भाग लें।

(3) उन मामलों में जहां समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात् निर्यातक धोखाधड़ी करने के लिए दोषी पाती है तो निर्यातक को विभिन्न अवधि के लिए हकदारियों प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने से विवर्जित किया जाये।

(4) गम्भीर मामलों में कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल एस आर टी ई पी सी, सचिव/डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए बगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थाई तौर पर विवर्जित किया जा सकता है।

(5) समिति को प्रवर्तन समिति कहा जायेगा तथा प्रवर्तन समिति के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपील समिति गठित की जायेगी जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा:—

- |   |             |
|---|-------------|
| संयुक्त सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय   | —अध्यक्ष    |
| विधि सचिव द्वारा यथा नामित अपर/           |             |
| संयुक्त कानूनी सलाहकार, विधि, न्याय तथा — |             |
| कंपनी कार्य मंत्रालय।                     | —सदस्य      |
| निर्यात आयुक्त                            | —सदस्य      |
| उप सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय        | —सदस्य-सचिव |

(6) प्रवर्तन अपील समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा टेक्सप्रोसिल/एस आर टी ई पी सी/डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी से अन्य ब्यौरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आदेशों

की समीक्षा, संशोधन, आशोधन कर सकती है अथवा उनको रद्द कर सकती है।

18. सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस: (1) प्रतिबंध अधीन उत्पाद

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों की तथा टेक्सप्रोसिल अथवा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत किसी अन्य उपयुक्त अभिकरण द्वारा अलग अलग माल के लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद दी जाएगी।

(2) हथकरघा उत्पाद

जहां तक प्रतिबंधित मर्चों के समानु रूप समस्त हथकरघा फ्रेमवर्क/मिडअप्स के निर्यात का संबंध है, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, वस्त्र समिति द्वारा संयोजन प्रपत्र के भाग-2 में "निरीक्षण संबंधी पृष्ठांकन" के आधार पर दी जाएगी।

(3) "इंडिया आईटम्स" के अंतर्गत आने वाले मेड-अप्स

"इंडिया आईटम्स" के संबंध में जोकि भारत की परंपरागत लोकरीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मर्चें हैं, उनका संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय, आर्थिक समुदाय, कनाडा, आस्ट्रिया, फिनलैंड तथा नार्वे को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर दी जाएगी।

19. निर्यात प्रमाण-पत्र, मूल स्थान का प्रमाण-पत्र तथा बीजा: टेक्सप्रोसिल अथवा उसकी ओर से विधिकत प्राधिकृत किसी अन्य निका द्वारा संबद्ध द्विपक्षीय वस्त्र करार के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणन जारी किए जायेंगे:—

(1) संयुक्त राज्य अमरीका

वाणिज्यिक मूल्य के समस्त मिल निर्मित/विद्युत्करघा क्रीब्रिक तथा मेड-अप्स के माल के लिए बीजा तथा श्रेणी 363, श्रेणी 369 के अंतर्गत आने वाले हथकरघा मेड-अप्स के लिए बीजा।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) विद्युत्करघा/मिल निर्मित उद्गम की सभी प्रति-बंधित मर्चों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र तथा उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) विद्युत्करघा/मिल निर्मित/बुनी हुई उद्गम की गैर प्रतिबंधित मर्चों के लिए मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

(3) कनाडा

500 कनेडियन डालर से कम मूल्य के माल को छोड़कर फ्रेमवर्क/मिडअप्स मर्चों, मिल निर्मित/विद्युत्करघा/बुनी हुई ऐसी मूल मर्चों के लिए जोकि प्रतिबंध अधीन है, निर्यात प्रमाणपत्र।

## (4) आस्ट्रिया

मिल निर्मित/विद्युत्करघा मूल के फ्रेमिकों/मेड-अप्स के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जो निगरानी अधीन होंगे।

## (5) नार्वे

श्रेणी 7 के अंतर्गत मूलतः विद्युत्करघा तथा मिल निर्मित चादरों के संबंध में निर्यात प्रमाणपत्र/मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

## (6) फिनलैण्ड

श्रेणी 7 के अंतर्गत मूलतः विद्युत्करघा तथा मिल निर्मित चादरों के संबंध में निर्यात प्रमाणपत्र/मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

20. हथकरघा पर छूट प्रमाणपत्र : कनाडा को प्रति-बंधित मर्दों के समनुरूप समस्त हथकरघा फ्रेमिकों/मेड-अप्स, आस्ट्रिया को सूती हथकरघा वस्त्र फ्रेमिक/मेड-अप्स, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमरीका को समस्त हथकरघा फ्रेमिक तथा मेड-अप्स तथा नार्वे और फिनलैण्ड को हथकरघा चादरों का निर्यात करने के मामले में ऐसे उत्पादों के लिए वस्त्र समिति द्विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी।

21. वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षकीय भूमिका : वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारियों के आबंटन से संबंधित मामलों का रोजाना पर्यवेक्षण करेगा। एक समन्वय समिति समय-समय पर नीति के प्रचालन की समीक्षा करेगी जिसमें वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऐसे मामलों पर जिनमें विचारों में मतभेद हो, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

22. सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। नीति में यथा आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी सरकार के पास सुरक्षित है, जोकि उरुगे वौर की वार्ताओं तथा मन्डी फाइबर व्यवस्था के भविष्य पर निर्भर करेगा।

23. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नोक्त अनुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,  
न्यू सी जी ओ बिल्डिंग, न्यू मेरीन लाईन्स,  
पोस्ट बाक्स नं. 11500,  
बम्बई-400 020.

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,  
इंजीनियरिंग सेंटर,  
5वां तल, 9 मेयू रोड,  
बम्बई-400 004

3. सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,  
रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड,  
बम्बई-400020

4. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,  
612, अशोका एस्टेट,  
24 बाराखम्भा रोड,  
नई दिल्ली-110001

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),  
वेस्ट ब्लॉक नं. 7, आर. के. पुरम,  
नई दिल्ली-110066

6. वस्त्र समिति,  
“क्रिस्टल” 79, डॉ. एनी बिसैट रोड,  
बोर्ली,  
बम्बई-400 018

एस. नारायणन, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1993

Subject : Conditions applicable for the period 1994-1996 for exports of certain Yarns, Fabrics and Made-up items to countries where such exports are covered under the bilateral agreements.

No. 1/4/93-EP(T&J) I.—1. Introduction.—Pursuant to the provisions contained in Item No. 11 of Appendix XLIII-J of Volume I of the Handbook of Procedures published under the Export and Import Policy (1992—1997), in respect of export of Yarn, Fabrics and Made-ups to USA, Canada, EEC, Austria, Finland and Norway the policy for allotment of entitlements, (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1994, 1995 and 1996 shall be as hereinafter detailed.

2. Administration.—Unless otherwise directed, the Executive Director, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) shall allocate entitlements of all Yarn, Fabrics and Made-up items, except for woollen yarn fabrics and made-ups, for which allotment will be made by the Secretary, Wool and Woollens Export Promotion Council (W&WEPC) and in respect of Cat. 3/EEC allotment of which will be made by the Executive Director, Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council (SRTEPC). However, necessary certification for all such exports shall be done by TEXPROCIL only.

(ii) For the purpose of the above, the Executive Director, TEXPROCIL, Secretary, W&WEPC and Executive Director, SRTEPC shall mean and include such other officials to whom they expressly or otherwise delegate part or whole of their functions and responsibilities.

(iii) The Executive Director, TEXPROCIL, the Secretary W&WEPC and Executive Director, SRTEPC, notwithstanding any delegation effected by them, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the Policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time, regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities under the Import-Export Policy.

3. Base Period.—The phrase "Base Period" for an allotment year wherever appearing in this Notification shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example the base period for the year 1994 shall be the year 1992.

4. Systems of Allotment.—(i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them.

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE) (of which High Value Entitlement)	55 (10)
(b) Manufacturer Exporter Entitlement (MEE)	15
(c) Ready Goods Exporters Entitlement (RGE)	15
(d) Non-Quota Exporters Entitlement (NQE) (of which NQE for handloom textiles)	10 (3)
(e) Powerloom Exporters Entitlement (PEE)	5
Total	100%

(ii) However the handloom made-up items under quantitative restraint in USA shall be allocated as follows :

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE) (of which High Value Entitlement)	55 (10)
(b) Ready Goods Exporters Entitlement (RGE)	35

(c) Non-Quota Exporters Entitlement (NQE) 10

100%

(iii) Apart from the above, quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under RGE System.

(iv) Government of India, in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case it is considered so desirable in view of changes in demand patterns.

(v) For allotments under PPE system including allotments of High Value items and NQE systems, the concept of Net Foreign Exchange (NFE) realisation will be adopted for allotments during 1995 and 1996. Detailed guidelines in this regard will be issued separately.

5. Past Performance Entitlement (PPE).—The agency for computation of PPE in respect of cotton yarn, fabrics and made-ups will be Executive Director, TEXPROCIL. In respect of Cat 3|EEC, ED, SRTEPC will be the concerned agency. Secretary, W&WEPC will be the concerned agency in respect of Cat 31.1 (Worsted Fabrics)|Canada Computation shall be done in the following manner.

(i) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports during the base period by the applicants in each country|category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country|category during the base period.

(ii) The average unit value realised by all exporters who have applied for PP Entitlement in a particular country|category during the base period would be worked out and exporters who have realised higher unit value than the average unit value will be allotted additional quantities from the 10% reserved pool (HVE) on the basis of their pro-rata share in exports.

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during its period of original validity. After 30th September, transfers are not allowed. The transferred PPE will be known as PPT.

(iv) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.

(v) Transfer of a PPT is not allowed.

6. Manufacturers Exporters Entitlement System.—

(i) Allotment under this system shall be made to manufacture-Exporters who have undertaken substantial modernisation and upgradation of technology in their plant and machinery during the base period. Guidelines and norms of eligibility will be separately notified by the Textile Commissioner.



(ii) The Textile Commissioner shall be the authority to decide the eligibility and production capacity of the Manufacturer-Exporters within the meaning of this system.

(iii) Allotment under this system shall be only in respect of goods manufactured in the production unit modernised and upgraded as determined by the Textile Commissioner.

(iv) Available quantity will be distributed by the Executive Director, TEXPROCIL on the basis of production capacity of eligible applicant as decided by the Textile Commissioner. Each eligible applicant may opt for a maximum of seven categories for the above allotment.

(v) When the quantity allotted to any applicant in any one category is too small (as decided by the Textile Commissioner), the Executive Director, TEXPROCIL shall reallocate such quantity in such manner that the quantities allotted to each of the applicants is reasonable enough.

(vi) Allotments under this system are not transferable. The allottees shall, at the time of certification of shipments submit an affidavit that goods being exported have been manufactured in his production unit so modernised/upgraded.

7. Ready Goods Exporters Entitlement (RGE) System.—(i) Quantities shall be allocated on first come-first-served basis against EMOBG @ 5 per cent of FOB Value.

(ii) On a particular day when available quantities are over-subscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the particular day.

(iii) Textile Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for each country/category under RGE System by an exporter in one day if the Textile Commissioner feels if necessary to do so.

8. Non-Quota Exporters Entitlement (NOE) System.—The agency for computation of NOE in respect of cotton yarn, fabrics and made-ups will be Executive Director, TEXPROCIL. In respect of Cat 3/EEC, ED, SRTEPC will be concerned agency Secretary, WVEPC will be the concerned agency in respect of Cat 31.1 (Worsted Fabrics)/Canada. Computation shall be done in the following manner :

(i) The Non-quota entitlements shall be distributed on the basis of the exports of yarn, fabrics and made-ups during the base year to non-quota countries and exports of non-quota items to quota countries provided the payment is received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 15 lacs during the base period.

(ii) Out of the entitlement of 10% reserved under this system, 7% will be common to all exporters and the remaining 3% will be exclusively for such exports pertaining to only handloom fabrics and made-ups.

(iii) Entitlement under this system shall be calculated on the basis of value of exports

during the base period and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants separately for yarn, fabrics and madeups.

(iv) An exporter shall be permitted a choice of seven countries/categories combination for allotment.

(v) All conditions applicable to PPE shall also be applicable for NQE, mutatis-mutandis.

(vi) NQE is transferable (hereinafter referred to as NQT) and the conditions of transfer will be the same as in case of PPE. NQT is not transferable.

9. Powerloom Exporters Entitlement (PEE) System.—Textile Commissioner will separately notify detailed guidelines and norms of eligibility for allotments under the PEE system.

10. (i) For the purpose of utilisation of allotments, there shall be a single period, viz. January-September in respect of PPE, NQE, PEE and MEE Systems. Exporters should utilise their entire allotments by 30th September. The unutilised quantities after 30th September can be extended upto 31st December of the same year against valid contract and EMD/BG @ 25% of the Minimum Export Price applicable to the item. Applications for extension of validity should reach ED TEXPROCIL during the period of the original validity of the entitlement.

(ii) The quantities earmarked in the above systems shall be opened on 1st January of the quota year and for this purpose applications may be invited during the previous year.

(iii) Entitlements under the RGE System shall be opened four times in the year on predetermined dates during the months of January, April, July and October. 75% of the level will be released during January, April and the balance 25% during July and October.

(iv) In case additional quantities become available for allotment under this system between the predetermined dates, such quantities shall be released any time after giving a notice of 15 days to the trade by the concerned Agency with the approval of Ministry of Textiles.

11. Validity of Certification.—Validity of certification under PGE Systems will be for a period of 30 days. Validity of Certification under PPE/MEE/NOE/PEE and transferred PP and NO Entitlements will be 30 days or till the expiry of the entitlement certificate whichever is earlier. The Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

12. Minimum Export Price (MEP).—The Textile Commissioner will fix Minimum Export Prices (MEPs) for various categories that are subject to quantitative restraint under all systems. While fixing

floor prices, the average unit value realisation in the recent past, the trends in utilisation of the annual levels and the fluctuations in exchange rates shall be taken into consideration.

13. Slow-moving items.—(i) An item shall be notified as slow-moving if during the base period its utilisation has been less than 75% of the base level for that year. The Executive Director, TEXPROCIL shall notify the items that are slow moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, for slow-moving items, EMD/BG where applicable, would be charged @ 1% of FOB value for shipments under the Ready Goods Entitlement (RGE) System.

This relaxation may, however, be withdrawn without advance notice.

16. Forfeiture of EMD/BG.—(i) The EMD/BG of an exporter who exports 90% or more of the entitlement would be released in full.

(ii) The EMD/BG of an exporter who exports less than 90% of the export entitlement including PPT/NOT, shall be forfeited as hereinafter provided. The Executive Director, TEXPROCIL shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75% in case of fast moving items and upto 50% in case of slow-moving items proportionate to the shortfall in utilisation. If utilisation is less than the above, the EMD/BG shall be forfeited in full.

(iii) For this purpose, utilisation shall be calculated on the basis of each period/system separately. In case of extension of validity/certification, percentage utilisation shall be computed separately for the quantity for which certification/validity has been extended.

(iv) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a Public Deposit Account of Government to be operated in such manner as Government decides from time to time.

(v) Persons to whom export entitlements are allocated but who do not utilise these fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(vi) A notice for show cause shall be issued before forfeiture.

(vii) If an exporter surrenders his entitlements under any system either during the original validity period or within a period of 3 days of the expiry of the original validity, 50 per cent of the EMD/BG covered by the entitlement would be released to the exporter.

15. Appeal against forfeiture of EMD/BG.—An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by Executive Director TEXPROCIL/SRTEPC under para 14 above may appeal before the Textile Commissioner within 60 days of despatch of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner

shall, upon receipt of such representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he will take into consideration the conditions of forfeiture spell out in the notification, in addition to force majeure conditions. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officer designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for by the applicant. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 60 days of the despatch of the communication conveying the decision, to the Appellate Committee, Ministry of Textiles.

16. Guidelines for obtaining release of held-up consignments:—(a) Where a shipment effected in a non-quota item or in another restrained item is reclassified by the importing country into a restrained category, EC/Visas for the reclassified category should be issued after the exporter surrenders the necessary quota in any system other than FCFS. If FCFS balance is available for allotment, EC/Visas may be issued without the exporter surrendering any quota, by debiting to such FCFS balance. The stipulations of this para will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected in FCFS system or in any of the other systems after obtaining extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required.

(b) Where a shipment exported in a restrained category is reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions:—

(i) The exporter returns the original EC/Visa that had been issued to him.

(ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export remains valid for the concerned quantity when the add back is requested.

(c) In (a) above the floor price of the reclassified category should be realised. This condition, however, may be relaxed by the Textile Commissioner in deserving cases.

(d) In cases where the exporter is required to surrender quotas for reclassified categories, he should also be allowed to do so from his own entitlements in PPE/NOE or MEE or entitlements obtained by transfer. If the case is to be cleared after the 1st of October, when transfers are not permissible and the exporter does not have his own entitlements to surrender, he may furnish an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31st of January from the succeeding years entitlement (his own or transferred). Such an undertaking should be backed by EMD/BG to the extent of 50 per cent of the value of the quantity calculated at the floor price value. In such cases, PP, NO, ME allotments in any country/category to the exporter for the succeeding year may be allotted only after the requisite quantity is surrendered. If the quantity is not surrendered, the EMD/BG may be forfeited.

17. Procedure to deal with Quota malpractices by exporters.—(i) Exporters who are found to have indulged in any fraudulent activity in connection with obtaining, utilising or proving the utilisation of quotas, may be issued show-cause Notices for explaining their conduct.

(ii) The cases shall be considered by a Committee with the following composition :—

- |    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
| 1  | The Textile Commissioner                     | — | Chairman         |
| 2. | Chairman, TEXPROCIL                          | — | Member           |
| 3. | Deputy Chairman and Vice Chairman, TEXPROCIL | — | Members          |
| 4. | Executive Director TEXPROCIL                 | — | Member           |
| 5. | Secretary, TEXPROCIL                         | — | Member Secretary |

If the Committee considers cases relating to malpractices in respect of export of category 3 (EEC). Cat. 31a (Canada), Chairman and ED of SRTEPC|Chairman and Secretary of WVEPC would be requested to participate in the meeting of the Committee as the special invitees.

(iii) In cases where the Committee finds the exporter guilty of fraud after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.

(iv) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by ED, TEXPROCIL|SRTEPC, Secretary, WVEPC before personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.

(v) The Committee will be called the Enforcement Committee and for hearing appeals against the decisions of the Enforcement Committee, an Enforcement Appellate Committee will be constituted with the following composition :—

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Joint Secretary (Exports),<br>Ministry of Textiles  | — | Chairman         |
| Additional Joint Legal Advisor<br>Ministry of Law, Justice and<br>Company Affairs as nominated<br>by Law Secretary. | — | Member           |
| Export Commissioner   | — | Member           |
| Deputy Secretary (Exports)<br>Ministry of Textiles  | — | Member Secretary |

(vi) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committee on appeal from the exporter or by calling for the details from TEXPROCIL|SRTEPC|WVEPC, on its own.

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the TEXPROCIL or any other appropriate agency designated for this purpose.

(ii) Handloom Products.

In so far as export of all handloom fabrics|made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the customs on the basis of 'Inspection endorsement' by the Textile Committee in part-2 of the combination form.

(iii) Made-ups falling under "India Item" : In respect of "India Items" which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for export to USA, EEC, Canada, Austria, Finland and Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Officers of the Development Commissioner (Handicrafts).

19. Export Certificate, Certificate of Origin & Visa: The following certification required under relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by TEXPROCIL or any other body duly authorised in this behalf.

- (i) USA.—Visa for all mill made|powerloom fabrics and made-ups consignments of commercial value and visa for handloom made-ups falling under cat 363, Cat 369.
- (ii) EEC.—(a) Export Certificate and Certificate of Origin for all restrained items of powerloom|mill made origin.  
(b) Certificate of origin for non-restrained items of powerlooms|mill made|knitted origin.
- (iii) CANADA.—Export Certificates for Fabrics|Made-up items, millmade|powerloom|knitted origin which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian dollar 500|/-.
- (iv) AUSTRIA.—Export certificates for fabrics|made-ups of mill made|powerloom origin subject to surveillance.
- (v) NORWAY.—Export Certificate|Certificate of Origin in respect of bedlinen of powerloom and millmade origin under Category 7.
- (vi) Finland.—Export Certificate|Certificate of Origin in respect of bedlinen of powerloom and millmade origin under Category 7.

20. Handloom Exempt Certificate.—In the case of export of all handloom fabrics|made-ups corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom textile fabrics|made-ups to Austria, all handloom fabrics and made-ups to EEC and the USA and handloom bedlinen to Norway and Finland, the Textile Committee will issue the Certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

18. Clearance by Customs.—(i) Products under restraint.

21. Supervisory role of Textiles Commissioner.—Textile Commissioner, Bombay shall exercise day-to-day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with Textile Commissioner as Chairman and representatives of Cotton Textiles Export Promotion Council and Handloom Export Promotion Council will review the operation of the policy periodically. On matters where there is differences of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

22. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice. Government also reserves the right to amend the policy, as necessary depending upon the outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of Multi Fibre Arrangement.

23. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. Office of the Textile Commissioner  
New C.G.O. Building, New Marine Lines  
Post Box No. 11500  
BOMBAY-400020.
2. The Cotton Textile Export Promotion Council  
Engineering Centre, 5th Floor,  
9 Mathew Road,  
BOMBAY-400004.
3. Synthetic & Rayon Textile Export Promotion Council,  
Resham Bhavan,  
78 Veer Nariman Road,  
BOMBAY-400020.
4. The Wool & Woollen Export Promotion Council,  
612 Ashoka Estate,  
24 Barakhamba Road,  
NEW DELHI-110001.
5. Development Commissioner  
(Handicrafts)  
West Block No. 7, R.K. Puram,  
NEW DELHI-66.
6. Textiles Committee,  
"Crystal", 79 Dr. Annie Besant Road,  
Worli, BOMBAY-400018.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1993

विषय :—द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत आने वाले देशों को परिधान तथा निटवियर निर्यात करने के लिए वर्ष 1994-1996 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्तें।

सं० 1/29/93-ईपी (टी एण्ड जे) 1 :—1. प्रस्तावना : परिधान तथा निटवियर के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आस्ट्रिया, फिनलैंड तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात तथा आयात नीति (1992-1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के खण्ड 1 के परिशिष्ट 43-जे की मद्द संख्या 11 में निहित उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 1994 से 1996 के लिए हकदारियों के आवंटन संबंधी नीति (जिसे इसके पश्चात् आवंटन नीति कहा गया है) वह होगी जो इससे इसके पश्चात् व्यौरेवार है।

2. प्रशासन : (1) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, निर्यात हकदारियों का आवंटन करेगा। इस आवंटन नीति के अन्तर्गत आने वाले सिले सिलाए परिधानों तथा निटवियर के सभी निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण भी महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद का अभिप्राय उनसे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें वो अपने ऐसे कार्य तथा उत्तरदायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें।

(3) महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आवंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के निर्वाचन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अभिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे अधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनर्आवर्तित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आवंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को दिया जाएगा जो आयात-निर्यात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

3. आधार अवधि : इस अधिसूचना में किसी भी स्थान पर आने वाले 'आधार अवधि' वाक्यांश का अभिप्राय किसी भी आवंटन वर्ष के लिए उस कलेण्डर वर्ष से होगा जो उस आवंटन वर्ष के पूर्व वर्ष से ठीक पहले आया हो। उदाहरणार्थ, वर्ष 1994 के लिए आधार वर्ष 1992 का वर्ष होगा।

4. आवंटन की प्रणाली : (1) प्रत्येक आवंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आवंटन निम्नलिखित प्रणाली के

अन्तर्गत प्रत्येक मद के सामने दिखाई गई दरों पर किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) विगत निर्यात हकदारी (पीपीई) (जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	70 (10)
(ख) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई) (जिसमें से वन निर्यातकों के लिए एम ई ई)	20 (2)
(ग) गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (हथकरवा वस्तुओं के लिए एन क्यू ई में से)	10 (2)
योग :	100

(2) समय समय पर अभ्यर्पणों, लोचशीलताओं या अन्यथा उपलब्ध होने वाली मात्राओं को पहले आओ पहले पाओ आधार के अन्तर्गत आबंटन किया जाएगा। ये मात्राएं महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा घोषित की जाने वाली पूर्व निर्धारित तारीखों को रिलीज की जाएगी। जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान कोई मात्रा रिलीज नहीं की जाएगी सिवाय उन मदों के जिनको कम कारोबार वाली मदों के रूप में अधिसूचित किया गया है। उनके लिए रिलीज 1 जनवरी को की जाएगी।

(3) मांग पैटर्न और अन्य सम्बद्ध कारकों में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आबंटन करने का अधिकार भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा।

(4) वस्त्र आयुक्त निटवियर, ऊनी उत्पादों, बाल परिधानों या अन्य उत्पादों के लिए मात्रा आरक्षित करेगा।

(5) उच्च मूल्य की मदों तथा गैर-कोटा निर्यात प्रणालियों के आबंटन सहित विगत निर्यात हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान सकल विदेशी मुद्रा वसूली की संकल्पना को अपनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त अलग से जारी किए जाएंगे।

5. विगत निर्यात हकदारी (पीपीई) प्रणाली : (1) महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद विगत निर्यात हकदारी का परिकलन निम्नलिखित आधार पर करेगा।

(2) उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदन कर्तियों द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, आबंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त देश/श्रेणी में भारत के वार्षिक औसत निर्यात की सीमा तक प्रति-बंधित कर दिया जाएगा।

(3) जिन निर्यातकों ने आधार अवधि के दौरान किसी देश/श्रेणी विशेष में विगत निर्यात हकदारी के लिए आवेदन

किया है उन सभी निर्यातकों की औसत इकाई मूल्य वसूली का निर्धारण किया जाएगा तथा औसत मूल्य से उच्चतर इकाई मूल्य वसूल करने वाले निर्यातकों को, निर्यात में उनके अंशदान के समानुपात में 10 प्रतिशत आरक्षित पूल (एच वी ई) में से अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया जाएगा।

(4) विगत निर्यात हकदारी को 20 सितम्बर तक आंशिक रूप से या पूर्णतया अंतरण किया जा सकेगा। अंतरण के लिए आवेदन पत्रों को महानिदेशक अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उन कोटा एजेंटों के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा जो उसके पास पंजीकृत होंगे। महानिदेशक, ए ई पी सी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोटा एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। जो कोटा एजेंट निर्यात हकदारी से संबंधित धोखा-धड़ी की कार्रवाई में लिप्त पाया जाएगा उसे इस अधिसूचना के पैराग्राफ 17 की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अवधि के लिए कोटा एजेंट के रूप में हकदारी के अन्तरण करने के कार्य में विरहित कर दिया जाएगा। अन्तरण के आवेदनों को महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किया जाएगा जिन्हें महानिदेशक, ए ई पी सी से प्राप्त किया जा सकता है। इन आवेदन पत्रों को दाखिल करने का वैध अवधि इसके जारी होने की तारीख से 15 दिन की होगी।

(5) अन्तरित विगत निर्यात हकदारी (इसके पञ्चस्त जिसका उल्लेख पी पी टी के रूप में किया जायेगा) उस वर्ष के 30 सितम्बर तक वैध रहेगा और उसे 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है जोकि निम्नलिखित पैरा 9(क)(1) के उपबन्धों के अधीन होगा।

(6) पीपीटी के आधार पर पोत लदानों को गणना हस्तांतरणकर्ता द्वारा विय समय निर्यात के रूप में की जायेगी।

(7) पी पी टी के हस्तांतरण को अनमति नहीं है।

6. विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई) प्रणाली  
(1) वस्त्र आयुक्त किसी विनिर्माता निर्यातक को पात्रता तथा उत्पादन क्षमता का निर्धारण करने के लिये प्राधिकारी होगा।

(2) वस्त्र आयुक्त एम ई ई के अन्तर्गत आबंटन के लिय किसी निर्यातक को पात्र होने के लिए सिलाई की मशीनों तथा कामगारों के अनुसार न्यूनतम क्षमता का निर्धारण करेगा। संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करते समय वस्त्र आयुक्त स्थापित की गई अन्य मशीनों को भी उचित महत्व देगा। वस्त्र आयुक्त कामगारों की संख्या तथा स्थापित की गई मशीनों की संख्या के बीच उपयुक्त परस्पर संबंधों के बारे में अपने आपकी भी सन्तुष्ट करेगा।

(3) एम ई ई के अन्तर्गत आबंटन केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में होगा जिनका उत्पादन मालिक की फैक्ट्री में किया गया हो। लीज होल्ड की फैक्ट्रियों सहित अन्य फैक्ट्रियों में उत्पादित वस्तुएं एम ई ई के लिये पात्र नहीं होंगी।

(4) सभी देशों/श्रेणियों के लिये उपलब्ध मात्राओं का सैद्धांतिक वितरण महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा यथा समानुपात आधार पर किया जायेगा जो कि वस्तु आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित पात्र आवेदकों की उत्पादन क्षमता के आधार पर होगा। ऐसे सैद्धांतिक आबंटनों को ऐसी श्रेणियों के बीच में उन अलग-अलग नियतकों में वितरित किया जायेगा जिनका ऐसी श्रेणियों के लिये पी पी ई की सम्पत्ति उनके आबंटन वर्ष से पहले के वर्ष के दौरान विगत निर्यात हकदारी 1,000 नग या उससे अधिक रहा हो। उन देशों/श्रेणियों, जिनमें मात्राओं को इस प्रकार वितरित किया जायेगा यदि वह उपलब्ध एम ई ई के स्तर को पार करता है तो अलग-अलग नियतकों को किये जाने वाले आबंटन को समानुपात में कम कर दिया जायेगा ताकि एम ई ई के स्तर के लिए कुल आबंटनों को सीमित रखा जा सके।

(5) जब किसी भी श्रेणी में किसी आवेदक को आबंटित की गई मात्रा (वस्तु आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित) बहुत कम होती है, महानिदेशक, ए ई पी सी ऐसे तरीके से ऐसी मात्रा को पुनर्आबंटन करेगा ताकि प्रत्येक आवेदक को आबंटित की गई मात्रा उचित रूप से पर्याप्त हो।

(6) नव निर्यातकों के लिये वार्षिक लक्ष्य का 2 प्रतिशत का आबंटन किया जायेगा और आबंटन आवेदक द्वारा चुने गये पांच देशों/श्रेणियों में उत्पादन क्षमता के यथा अनुपात के आधार पर किया जायेगा। नव निर्यातक वे हैं जिन्होंने आबंटन वर्ष से पहले के वर्ष के दौरान विगत निर्यात हकदारी सभी देशों/श्रेणियों के लिये एक साथ शून्य से लेकर 1,000 नग या और उनको इससे पहले एम ई ई का आबंटन नहीं किया गया था।

(7) विनिर्माता निर्यातक हकदारी हस्तांतरणीय नहीं है। किसी इकाई को वर्ष विशेष में एम ई ई का आबंटन करने से पूर्व मालिक/प्रबन्धक सहभागी/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा कि (क) पिछले वर्ष के दौरान एम ई ई का उपयोग, यदि कोई हो, तो वह उन वस्तुओं के लिये किया गया था जिनका उत्पादन उसकी अपनी इकाई में किया गया हो जिनके प्रति एम ई ई का आबंटन किया गया है और (ख) और वह हकदारी के लिये वस्तुओं का उत्पादन जो कि उसको अब आबंटित होगी उस इकाई में किया जायेगा जो कि उसकी अपनी स्वयं की हो।

(8) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन वास्तविक विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, वस्तु आयुक्त इस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन के लिये पात्र पाई गई आवेदक की सभी इकाइयों का नीति अवधि के दौरान अधिकारियों के दल द्वारा कम से कम एक बार निरीक्षण कर पायेगा ताकि उसकी स्थापित क्षमता की जांच की जा सके। नव नियतकों के लिये आरक्षित 2 प्रतिशत के लक्ष्य में से एम ई ई का उपयोग करने वाली इकाइयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण किया जायेगा। वह विशेषज्ञ सनदी लेखाकारों द्वारा एम ई ई धारकों की इकाइयों की जांच करवाने की भी व्यवस्था करेगा।

7. गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) प्रणाली :-

(1) गैर-कोटा देशों को परिधान तथा कोटा देशों को गैर-कोटा मर्च के निर्यातक इस प्रणाली के अन्तर्गत पात्र होंगे वशर्ते कि भुगतान मुक्त मुद्रा में प्राप्त किया गया है और निर्यातक का आधार अवधि के दौरान न्यूनतम निर्यात निष्पादन 15 लाख रु. को हो।

(2) इस प्रणाली के अन्तर्गत हकदारी का परिचालन और आबंटन महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा आधार अवधि के दौरान निर्यातों के मूल्य के आधार पर किया जायेगा और उपलब्ध लक्ष्यों को यथा-अनुपात अलग-अलग आवेदकों के निर्यात की कीमत के आधार पर वितरित किया जायेगा।

(3) एक निर्यातक को आबंटन के लिये सात देशों/श्रेणियों के मिश्रण के विकल्प की अनुमति होगी।

(4) विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) पर लागू होने वाली सभी शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) पर भी लागू होंगी।

(5) गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) हस्तांतरणीय है (जिसे इसके पश्चात् एन क्यू टी के रूप में उल्लिखित किया गया है) तथा अंतरण की शर्तें वही होंगी जो कि पी पी ई के मामले पर लागू होती हैं। एन क्यू टी अहस्तांतरणीय है।

8. पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) प्रणाली :- (1) मात्राओं को आवेदन प्रस्तुत करने पर पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के आधार पर आबंटित किया जायेगा। आवेदन पत्रों के साथ साख-पत्र संलग्न होने चाहिये जोकि आवेदन की तारीख को वैध हो। आबंटन 60 दिन के लिये वैध होगा और उसके पश्चात् समय वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(2) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन अन्तर्निहित मात्रा की एफ ओ बी की कीमत का 5 प्रतिशत की दर से ई एम डी/बी जी के अध्यधीन होगा।

(3) वस्त्र आयुक्त उस अधिकतम मात्रा का निर्धारण करेगा जो कि किसी आवेदनकर्ता द्वारा इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रत्येक देश/श्रेणी को सप्लाई किए जा सकते हों।

(4) आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे और जिस दिन जब उपलब्ध मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक हो, पात्रता का निर्धारण उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से उच्च इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जायेगा।

(5) पहले आओ पहले पाओ आवंटन हस्तांतरणीय नहीं है।

9. आवंटन की अवधि :—(क) पी पी ई, एम ई ई तथा एन क्यू ई प्रणालियां :

(1) आवंटन उपयोग के प्रयोजनार्थ पी पी ई, एम ई ई तथा एन क्यू ई प्रणालियों के अन्तर्गत 1 जनवरी से 30 सितम्बर तक की एकल अवधि होगी। निर्यातकों को अपनी हकदारियों का 30 सितम्बर तक उपयोग कर लेना चाहिये। 30 सितम्बर के पश्चात् उपयोग न की गई मात्रा का उसी वर्ष के 31 दिसम्बर तक 30 प्रतिशत की दर के ई एम डी/बी जी के साथ इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि मांगी गई समय वृद्धि एक विशिष्ट क्रेता के लिए है और क्रेता को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) इन प्रणालियों में उद्दिष्ट की गई मात्राएं 1 जनवरी को खोली जायेंगी तथा इस प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र विगत वर्ष के दौरान आमंत्रित किये जा सकते हैं।

10. शिपिंग बिलों के प्रमाणन की वैधता :—(1) हस्तांतरित पी पी तथा एन क्यू हकदारियों सहित पी पी ई, एम ई ई तथा एन क्यू ई प्रणालियों के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणन की अवधि 60 दिनों अथवा हकदारी प्रमाणपत्र की वैधता इसमें से जो भी पहले हो, तक होगी। इनकी पुनः वैध कराने की अनुमति हकदारी प्रमाणपत्र की समाप्ति तक ही दी जायेगी।

(2) पहले आओ पहले पाओ आवंटनों के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणपत्र की वैधता, आवंटन की तारीख से 60 दिनों के लिये होगी। इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) इस पैरा में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद वस्त्र आयुक्त अलग-अलग मामलों में तीन कार्य दिवसों तक वैधता अवधि को बढ़ा सकते हैं। यदि वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संबंधित निर्यातक अपने निर्यात से बाहर परिस्थितियां होने के कारण अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका।

11. कम कारोबार वाली मदें :—(1) किसी मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में अधिसूचित किया जायेगा यदि आधार अवधि के दौरान उसका उपयोग, उक्त वर्ष के आधार स्तर के 75 प्रतिशत से कम रहा हो। महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संबंधन परिपद पिछले वर्ष के अधिक से अधिक 1 दिसम्बर तक उन मदों को अधिसूचित करेगा जो कम कारोबार वाली मदें हैं।

(2) इस अधिसूचना के किसी भी उपबन्ध में अन्यत्र निहित प्रावधान के बावजूद सामान्यतः कम कारोबार वाली मदों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी :

(क) निर्यातक को पहले आओ पहले पाओ के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों के लिये निर्धारित दरों के बजाय 1 प्रतिशत ई एम डी/बी जी प्रतिशत करनी होगी।

(ख) उपर्युक्त पैरा 8 के अन्तर्गत पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के लिये निर्धारित मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी।

(2) वस्त्र आयुक्त द्वारा चालू मांग पैटर्न के आधार पर बिना कोई पूर्व सूचना दिये उपर्युक्त किसी भी रियायत को वापिस लिया जा सकता है।

12. निम्नतम कीमतें :—(1) वस्त्र आयुक्त उन विभिन्न देशों/श्रेणियों के लिये निम्नतम कीमतें निर्धारित करेंगे जो कि मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों के अधीन हैं।

(2) निम्नतम कीमत निर्धारित करते समय हाल ही में वसूल किये गये औसत इकाई मूल्य, मात्राओं के उपयोग की प्रवृत्तियों तथा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जायेगा।

13. हथकरघा परिधान :—कुछ देशों के लिये द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत हथकरघा परिधानों के लिये आरक्षित विशेष मात्राएं पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित की जायेंगी।

14. पेशगी जमा राशि बैंक गारंटी (ई एम डी/बी जी) प्रस्तुत करने तथा जस्त करने के संबंध में उपबन्ध—

(1) पी पी ई, एम ई ई तथा एन क्यू ई प्रणालियों के मामले में निर्यातकों को हकदारी की मूल वैध अवधि के दौरान पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी। तथापि, 30 सितम्बर, तक अप्रयुक्त मात्राओं को ई एम डी/बी जी की 30 प्रतिशत की दर से 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है (इस दर को लागू निम्नतम कीमतों के आधार पर परिकलित किया गया है)।

(2) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के मामले में एक निर्यातक को आवेदित मात्राओं पर एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से ई एम डी/बी जी देनी होगी।

(3) जिन निर्यातकों की पी पी ई तथा एम ई ई अवधि एन क्यू ई की प्रणालियों में से किसी भी प्रणाली में निहित सभी श्रेणियों के लिये हकदारियां 25,000 नग से कम नहीं है उनको ई एम डी/बी जी के स्थान पर कानूनी परिवर्तन (एल यू टी) प्रस्तुत करने का विकल्प होगा जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) ई एम डी/बी जी के स्थान पर एल यू टी प्रस्तुत करने की सुविधा पी पी ई, एन क्यू ई तथा एम ई ई प्रणालियों सहित पी पी टी तथा एन क्यू टी में प्राप्त निर्यातकों के हकदारियों की अवधि बढ़ाने/अवधि को पुनर्विध करने पर दी जायेगी। पहले आधे पहले पाओ प्रणाली में यह सुविधा आक्टन के लिये प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) यदि महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद् कानूनी परिवर्तन के अन्तर्गत शामिल की गई हकदारियों के लिये किसी भी राशि को जमा करने का दावा निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत करते हैं तो उस स्थिति में संबंधित निर्यातक जिसने कि कानूनी परिवर्तन प्रस्तुत किया था, डी जी, ए ई पी सी द्वारा इस प्रकार से किये गये दावे की राशि को ऐसे दावे की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर जमा करा देगा। ऐसा न करने पर निर्यातक शिपिंग बिलों के किसी भी प्रमाणन के आवेदन अथवा प्राप्त करने के लिये, हकदारियों के अन्तरण के लिये अथवा किसी भी प्रणालियों में ई एम डी/बी जी को वापिस करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उक्त राशि न जमा कर दे तथा डी जी, ए ई पी सी निर्यातक के लिये सुविधाएं बहाल करने का निर्णय न ले ले।

(ग) डी जी, ए ई पी सी ऐसे किसी भी निर्यातक के लिये ई एम डी/बी जी के स्थान पर एल यू टी प्रस्तुत करने की सुविधा वापिस ले सकता है जो कि इस सुविधा के लिये प्रमाण प्राप्त है लेकिन वे 90 दिनों की निश्चित अवधि के भीतर जमा की गई किसी भी प्रकार की राशि को जमा करने में असफल रहता है।

(घ) ई एम डी/बी जी पर लागू मार्ग निर्देशी सिद्धान्त तथा शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित एल यू टी पर भी लागू होंगी।

(4) ऐसा निर्यातक जो कि निर्यात हकदारी का कम से कम 90 प्रतिशत का निर्यात करता है, उसकी ई एम डी/बी जी की पूरी राशि रिलीज कर दी जाएगी। डी जी, ए ई पी सी अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75 प्रतिशत तक तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50 प्रतिशत तक उपयोग किये जाने की स्थिति में उपयोग में जितनी कमी रही है उसके समानुपात ई एम डी/बी जी जम्मा कर लेगा। यदि निर्यात हकदारी आक्टन का उपयोग उपरोक्त प्रतिशत से कम रहता है तो ई एम डी/बी जी की पूरी राशि जम्मा कर ली जायेगी। इस प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकलन अलग-अलग हकदारियों अथवा प्रत्येक प्रणाली के आधार पर अलग-अलग किया जायेगा।

(5) यदि एक निर्यातक पहले आधे पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत या तो मूल वैधता अवधि के दौरान अथवा मूल वैधता अवधि की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी हकदारियां वापिस कर देता है तो ई एम डी/बी जी अथवा एल यू टी में लागू राशि का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया जायेगा।

(6) ई एम डी/बी जी की जम्मा की गई समस्त राशि सरकार के पब्लिक डिपॉजिट खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका संचालन ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसा सरकार समय-समय पर निर्णय करेगी।

(7) अवधि बढ़ाने के लिए सभी आवेदन पत्र, मूल हकदारी की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले अथवा हकदारी की समाप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवसों की रिमायन्सी अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूरा भर करके प्रस्तुत करने होंगे।

15. ई एम डी/बी जी के खिलाफ अपील :—एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 14(4) के अन्तर्गत महानिदेशक, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जम्मा की गई राशि से हानि पहुंचती है तो वह जम्मा की गई राशि के सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्तु आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्तु आयुक्त ऐसे अपील के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा। अपीलों को निपटाने के समय वह अपरिहार्य घटना की स्थितियों के अलावा अधिसूचना में परिभाषित जम्मा की शर्तों को भी ध्यान में रखेगा। इस प्रयोजन के लिए वस्तु आयुक्त से अभिप्राय वस्तु आयुक्त तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए अन्य अधिकारी से होगा।



## 16. रीके गए माल की रिलीज करवाने के लिए भाग-

दर्शी सिद्धांत :—(क) जहां आयातक देश द्वारा लदान की गई गैर-कोटा श्रेणी अथवा किसी अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो वहां पुनर्वर्गीकृत श्रेणी के लिए ई सी/वीजा, निर्यातक द्वारा पहले आओ पहले पाओ प्रणाली को छोड़कर किसी भी प्रणाली में आवश्यक कोटा को वापिस किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। यदि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में आबंटन के लिए हकदारियां अधिशेष रहती हैं तो उस स्थिति में निर्यातक द्वारा कोई कोटा वापिस किए बिना पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अधिशेष में नामे डालकर ई सी/वीजा जारी कर दिया जाये। इस पैरा के अनुबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें पोतलदान के लिए खरीदार को बदलने की आवश्यकता हो जोकि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में या 30 सितम्बर के बाद समय वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य प्रणाली से प्रभावित हुआ हो तथा उन मामलों में जिनमें आयातक देशों में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

(ख) जब प्रतिबंधित श्रेणी की निर्यात के लिए लदान की गई वस्तुओं को उपर्युक्त अनुसार अन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तब देश से जहाज से भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को वापिस की जाए :—

(1) निर्यातक उस मूल ई सी/वीजा को वापिस कर दे जोकि उसे जारी किया गया था।

(2) हकदारी प्रमाणपत्र, जिसे निर्यात के समय नामे डाला गया था, अनुरोध किए जाने पर संबंधित मात्रा के लिए वैध बना रहेगा।

(ग) उपर्युक्त (क) के मामले में पुनः वर्गीकृत श्रेणी की निम्नतम कीमत वसूल की जाए। तथापि, उपर्युक्त मामलों में वस्त्र आयकन इस शर्त में ढील दे सकता है।

(घ) ऐसी मदों के मामले में जिनमें आयातक देशों द्वारा प्रतिबंधित मदों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, यदि उन्हें प्रति-

बंधित मदों से छूट प्राप्त हुयकरवा परिधानों के रूप में अथवा "इण्डिया आइटम्स" के रूप में निर्यात किया जाता है तो डी जी, ए ई पी सी, वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वीजा/निर्यात प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

(ड.) जहां निर्यातक को पुनः वर्गीकृत श्रेणियों के लिए कोटा वापिस करना अपेक्षित होता है, ऐसे मामलों में उसे पी पी ई, एनक्यूई या एम ई ई में अपनी हकदारियों अथवा हस्तांतरण से प्राप्त की गई हकदारियों में से भी ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मामले का निपटान 1 अक्टूबर के बाद किया जाना है तथा अन्तरण करने की अनुमति नहीं है तथा वापिस करने के लिए निर्यातक के पास अपनी निजी हकदारियां नहीं हैं तो उस स्थिति में वह इस आशय का परिवचन प्रस्तुत करेगा कि वह उत्तरवर्ती वर्ष की हकदारी से (निजी या हस्तांतरित) 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा को वापिस कर देगा। ऐसे परिवचन पत्र के साथ (निम्नतम कीमत मूल्य पर परिकलित की गई) मात्रा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि को पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में उत्तरवर्ती वर्ष के लिए निर्यातक को किसी भी देश/श्रेणी में पी पी, एनक्यू, एम ई हकदारियों का आबंटन, अपेक्षित मात्रा वापिस करने के बाद ही किया जाए। यदि मात्रा वापिस नहीं की जाती है तो पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी जप्त कर ली जाये। मात्रा वापिस करते ही ई एम वी/वी जी रिलीज की जा सकती है। यदि दिए गए परिवचन के अनुसार मात्रा वापिस नहीं की जाती है तो ई एम डी/वी जी जप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में केवल अपेक्षित मात्रा वापिस करने के पश्चात् ही निर्यातक को उत्तरवर्ती वर्ष के लिए किसी भी देश/श्रेणी में पी पी, एनक्यू, एम ई के आबंटन किए जा सकते हैं।

17. निर्यातकों तथा कोटा एजेंटों द्वारा कोटा संबंधी अनाचार से निपटने की प्रक्रिया:—(1) जो निर्यातक कोटा प्राप्त करने, कोटा का उपयोग करने या कोटा के उपयोग को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की बेईमानी करने में लिप्त पाये जाते हैं, उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये जाएं।

(2) ऐसे मामलों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा:—

वस्त्र आयुक्त —अध्यक्ष

महानिदेशक, अपरैल निर्यात —सदस्य

संवर्धन परिषद्

अध्यक्ष, अपरैल निर्यात संवर्धन —सदस्य

परिषद्,

तीन उपाध्यक्ष, अपरैल निर्यात —सदस्य

संवर्धन परिषद्

वरिष्ठ निदेशक/निदेशक (क्यूपी), —सदस्य-सचिव  
अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद्

(3) उन मामलों में जहां समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात निर्यातक धोखाधड़ी करने के लिए दोषी पाती है तो निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए हकदारियां प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने से विवर्जित किया जाये।

(4) गम्भीर मामलों में महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए बगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अन्तिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थाई तौर पर विवर्जित किया जा सकता है।

(5) समिति को प्रवर्तन समिति कहा जायेगा तथा प्रवर्तन समिति के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपील समिति गठित की जायेगी जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा:—

संयुक्त सचिव (निर्यात), —अध्यक्ष  
वस्त्र मंत्रालय

विधि सचिव द्वारा यथा नामित —सदस्य  
अपर/संयुक्त कानूनी सलाहकार,  
विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य-  
मंत्रालय।

निर्यात आयुक्त —सदस्य

उप सचिव (निर्यात), —सदस्य-सचिव  
वस्त्र मंत्रालय

(6) प्रवर्तन अपील समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् से स्वयं व्यूरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आदेशों की समीक्षा, संशोधन, आशोधन कर सकती है अथवा उनको रद्द कर सकती है।

(7) इस पैरा के उपबन्ध ऐसे कोटा एजेंटों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जोकि निर्यात क्रियाकलापों से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने में लिप्त पाये जाते हैं।

18. सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस—(क) प्रति-बंधित मर्चों के अन्तर्गत उत्पाद जिनमें वे मर्च भी शामिल हैं जोकि संयुक्त राज्य अमरीका में विशिष्ट सीमाओं के अध्यधीन नहीं हैं।

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किये गये निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों तथा अलग अलग माल के लिये जारी किये गये शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद ही दी जायेगी।

(ख) हथकरघा परिधान—जहां तक सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात का संबंध है, जिसमें कनाडा में प्रतिबन्धित मर्चों के समतुल्य टेलर्ड कालर शर्ट्स शामिल नहीं हैं, आस्ट्रिया को सूती हथकरघा परिधानों और यू एस. ए. ई ई सी, नार्वे तथा फिनलैंड की प्रतिबन्धित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिये आरक्षित विशेष मात्राओं का पोतलदान की अनुमति डी जी, ए ई पी सी द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त संयोजन प्रमाणपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा किये गये निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी जायेगी।

(ग) “इण्डिया आइटम्स” के अन्तर्गत आने वाले परिधान —“इण्डिया आइटम्स” के संबंध में जोकि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मर्च हैं, उनका यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका, फिनलैंड, आस्ट्रिया, नार्वे तथा कनाडा को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किये गये उपयुक्त प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणन के आधार पर दी जायेगी।

19(क) निर्यात प्रमाण-पत्र, मूल स्थान का प्रमाण-पत्र तथा बीजा—महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा उनकी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी

भी एजेंसी द्वारा द्विपक्षीय वस्त्र करार के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे :—

#### 1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) प्रतिबन्धों के अंतर्गत समस्त परिधान/निटवियर मर्चों के लिये निर्यात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

(ख) समस्त गैर-प्रतिबन्धित परिधानों/मर्चों के लिये मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

#### 2. फिनलैंड

प्रतिबन्धित मर्चों के लिये प्रमाणपत्र।

#### 3. आस्ट्रिया

परिधानों के लिये निर्यात प्रमाणपत्र जो कि प्रतिबंध अथवा निगरानी के अध्वधीन है।

#### 4. नार्वे

विशिष्ट सीमाओं के अध्वधीन श्रेणियों के लिये निर्यात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र।

#### 5. कनाडा

निटिड, विद्युतकरघा तथा मिल निर्मित मूल के परिधानों के लिये निर्यात प्रमाणपत्र जो कि 500 अथवा उससे कम कनेडियन डालर के मूल्य के प्रेषित माल को छोड़कर प्रतिबंधों के अध्वधीन है।

#### 6. संयुक्त राज्य अमरीका

250 अथवा उससे कम अमरीकी डालर के मूल्य के विधिवत चिन्हित नमूनों को छोड़ करके समस्त परिधान/निटवियर माल के लिये बीजा।

#### (ख) हथकरघा प्रमाणपत्र :

सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के मामलों में, जिसमें कनाडा को प्रतिबन्धित मर्चों के समतुल्य टेलर्ड कालर शर्ट्स शामिल नहीं है, आस्ट्रिया को सूती हथकरघा परिधानों तथा ई ई सी, नार्वे, आस्ट्रिया तथा फिनलैंड को प्रतिबंधित कुछ श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिये आरक्षित विशेष मात्राओं के संबंध में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिये द्विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी।

20. ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारियां आवंटित की गई हैं लेकिन वे उनका पूर्णरूपण उपयोग नहीं करते हैं, वे अपने खिलाफ की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भविष्य में हकदारियां प्राप्त करने के लिये अपने आपको अयोग्य कराने के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

21. सरकार के पास पूर्व सूचना दिये बिना उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो नीति में संशोधन करने का अधिकार भी सरकार

के पास सुरक्षित है, जो कि उक्त दौर की वार्ताओं तथा मल्टीफाइबर व्यवस्था के भविष्य पर निर्भर करेगा।

22. अप्रैल निर्यात संबंधन परिपद तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र, समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नोक्त के अनुसार हैं :—

1. अप्रैल निर्यात संबंधन परिपद,  
सहयोग बिल्डिंग, चौथा तल,  
58, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली-110019
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,  
न्यू सी जी ओ कम्पलैक्स,  
न्यू मरीन लाइन्स,  
(पोस्ट बॉक्स नं. 11500),  
बम्बई-400020
3. वस्त्र समिति,  
"क्रिस्टल" 79, डा. एनो बेसेंट रोड,  
बम्बई-400018
4. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),  
वैस्ट ब्लॉक-7,  
रामकृष्णपुरम,  
नई दिल्ली-110066

एस. नारायणन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1993

Subject :—Conditions applicable for the period 1994-1996 for exports in respect of Garments and Knitwear to countries where such exports are covered under the bilateral agreements.

No. 1/29/93-EP(T&J)I.—1. Introduction :—Pursuant to provisions contained in Item No. 11 of Appendix XLIII-J of Volume I of the Handbook of Procedures published under the Export and Import Policy (1992-1997) in respect of export of ready-made garments and knitwear to USA, Canada, EEC, Austria, Finland and Norway, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1994 to 1996 shall be as hereinafter detailed.

2. Administration :—(i) Unless otherwise directed the Director General, Apparel Export Promotion Council, New Delhi (DG, AEPC) shall allocate export entitlements. DG, AEPC shall also do the necessary certification for all export of readymade garments and knitwear covered in this Allotment Policy.

- (ii) For the purpose of the above, the DG, AEPC shall mean and include such other officials of AEPC to whom DG, AEPC expressly or otherwise delegates part or whole of such functions and responsibilities.
- (iii) The DG, AEPC notwithstanding any delegations effected by her/him shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the allotment policy.
- (iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.
- (v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per Import-Export Policy.

3. Base Period :—The phrase “base period” for an allotment year, wherever appearing in this notification, shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example, the “base period” for the year 1994 shall be the year 1992.

4. Systems of allotment:—(i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated under the following systems at rates indicated against each of them :—

System	Percentage of Annual Level
(a) Past Performance Entitlement (PPE) (of which High Value Entitlement)	70 (10)
(b) Manufacturer Exporter Entitlement (MEE) (of which MEE for newcomers)	20 (2)
(c) Non Quota Exporters Entitlement (NQE) (of which NQE for handloom garments)	20 10 (2)
Total : 100	

- (ii) Quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall be allocated under First-Come-First-Served (FCFS) basis. Such quantities shall be released on pre-determined dates to be announced by DG, AEPC. No releases will be made during the period January—March except for items notified as slow moving items for which releases may be made on 1st January.
- (iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case it

is considered so desirable, in view of changes in demand pattern and other relevant consideration.

- (iv) The Textile Commissioner may reserve quantities for knitwear, woollen products, children's wear or any other segment.
- (v) Under PPE system including allotments of High Value entitlements and NQE System, the concept of Net Foreign Exchange (NFE) realisation will be adopted for allotments during 1995 and 1996. Detailed guidelines in this regard will be issued separately.

#### 5. Past Performance Entitlement (PPE) Systems:—

- (i) The DG, AEPC shall compute PPE on the following basis.
- (ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports during the base period by the applicants in each country/category. Allotments, however, will be restricted to the export performance of India in the country/category during the base period.
- (iii) The average unit value realised by all exporters who have applied for PP Entitlement in a particular country/category during the base period would be worked out and exporters who have realised higher unit value than the average unit value will be allotted additional quantities from the 10 per cent reserved pool (HVE) on the basis of their pro-rata share in exports.
- (iv) PPE shall be transferable, either in full or in part, upto 20th September. The applications for transfer of PPEs will be accepted by DG, AEPC through Quota Agents who are registered with DG, AEPC. DG, AEPC will make necessary arrangements for registration of Quota Agents, in terms of the guidelines issued by Government from time to time. Quota Agents who are found to have indulged in any fraudulent activity relating to export entitlements may be debarred from handling transfer of entitlements as Quota Agents for specified periods, in terms of paragraph 17 of this notification. The applications of the transferer will be received by DG, AEPC in the application forms to be obtained from DG, AEPC which would have a validity period of 15 days for being filed with DG, AEPC, from the date of its issue.
- (v) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid upto 30th September of the year and can be extended upto 31st December, subject to the provisions of para 9(a)(i) below.
- (vi) Shipments against PPT will be counted as exports by the transferee.
- (vii) Transfer of a PPT is not allowed.

## 6. Manufacturer Exporter Entitlement (MEE), System :—

- (i) The Textile Commissioner shall be the authority for deciding the eligibility and production capacity of a Manufacturer-Exporter.
- (ii) The Textile Commissioner shall prescribe the minimum capacity in terms of sewing machines and workers for an exporter to be eligible for allotment under MEE. While assessing relative capacity, Textile Commissioner shall also give due weightage to other machines installed. The Textile Commissioner will also satisfy himself about a reasonable correlation between the number of workers and machines installed.
- (iii) The allotment under MEE is in respect of goods manufactured in the factory of the owner only. Goods manufactured elsewhere including factories under leasehold shall not be eligible for MEE.
- (iv) Available quantities for all country/categories will be nationally distributed by DG, AEPC pro-rata on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textiles Commissioner. Such notional allotments to individual exporters will be distributed among the categories in which the applicants have past performance entitlements of 1,000 pcs or more during the year preceding the allotment year in proportion to their PPE holdings for such categories. In country/categories where the quantities so distributed exceed the MEE level available, the allotments to individual exporters will be scaled down proportionately in order to restrict the total allotments to the MEE level.
- (v) When it is observed that quantity allotment to one or more of Manufacturer-Exporters for a country/category is too small (as decided by Textile Commissioner) the D.G. AEPC may reallocate these quantities in such a manner that the quantity allotted to each of the applicants is reasonable enough.
- (vi) For new comers, 2 per cent of annual levels will be allotted and the allotments will be done on pro-rata basis on production capacity in 5 country/categories to be opted by the applicants. New comers are those who have past performance entitlements of nil to 10,000 pcs for all country/categories taken together, for the year preceding the allotment year and have not been allotted MEE in the past.
- (vii) MEE is not transferable. Before allocation of MEE to a unit in a particular year, the Proprietor/Managing Partner/Managing Director shall be asked to submit an affidavit to the effect that (a) the MEE utilised during the previous year, if any, was for goods physically manufactured by the units owned by him against which the MEE had been allotted and (b) he shall manufacture the goods for entitlement to be allotted now to him in units physically owned by him.

(viii) In order to ensure that allotments under this system are availed by genuine manufacturers, the Textile Commissioner shall cause all the units of applicants held eligible for allotment under this system to be inspected by a team of officers at least once during the policy period, with a view to verifying the installed capacities. Units, availing MEE from the 2 per cent level reserved for new comers shall be inspected on a priority basis. He may also arrange for verification of the units of MEE holders through specialised Chartered Accountants.

7. Non-Quota Exporters Entitlement (NQE) System.—(i) Exporters of apparel to Non-quota countries and non-quota items to quota countries shall be eligible under this system provided the payment is received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 15 lacs during the base period.

(ii) Entitlement under this system shall be calculated and allotted by DG, AEPC on the basis of value of export's during the base period and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.

(ii) An exporter shall be permitted a choice of five countries/categories combination for allotment.

(iv) Conditions applicable to PPE, shall also be applicable to NQE, *mutatis mutandis*.

(v) NQE is transferable (hereinafter referred to as NQT) and the conditions of transfer shall be the same as in the case of PPE. NQT is not transferable.

8. First-come-First-Served (FCFS) System :—(i) Quantities shall be allocated on First-Come-First-Served basis against applications supported by LC's valid on the date of application. Allotments will be valid for 60 days and no extension will be granted.

(ii) Allotments under FCFS system would be subject to EMD/BG @ 5 per cent of FOB value of the quantity involved.

(iii) Textile Commissioner will fix the maximum quantity that can be applied by any applicant for each country/category under this system per day.

(iv) Allotment shall be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the day.

(v) FCFS allotments are not transferable.

## 9. Period of allotment

(a) PPE, MEE and NQE Systems.—(i).—For the purpose of utilisation of allotments, there shall be a single period from 1st January to 30th September under PPE, MEE and NQE Systems. Exporters should utilise their entitlements by 30th September. The unutilised quantities after 30th September can be extended upto 31st December of the same year against EMD/BG @ 30 per cent (calculated on Floor Price) subject to the conditions that the extension sought is for a specific buyer and change of buyer will not be permitted.

(ii) The quantities earmarked in these systems shall be opened on 1st January and for this purpose, applications may be invited during the previous year.

10. Validity of certification on shipping Bills.—(i) Validity of certifications on shipping bills in respect of PPE, MEE and NQE Systems including transferred PP and NQ Entitlements will be 60 days or upto the validity of the entitlement certificate, whichever is earlier. Revalidation will be permitted upto the expiry of the entitlement certificate.

(ii) Validity of certification on shipping bills in respect of FCFS allotments would be 60 days from the date of allotment. No extension will be permitted.

(iii) Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

11. Slow moving items.—(i) An item may be declared to be slow-moving if during the base period, its utilisation has been less than 75 per cent of the base level. The Director General, AEPC shall declare the items that are slow moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, the following relaxations shall ordinarily be available for slow moving items :—

(a) The exporter will have to furnish 1 per cent EMD|BG instead of the rates stipulated for other categories under FCFS.

(b) The quantitative ceiling stipulated for FCFS vide para 8 above shall not be enforced.

(iii) Any of the above relaxations may be withdrawn without advance notice by the Textile Commissioner on the basis of current demand pattern.

12. Floor Prices.—(i) The Textile Commissioner, will fix floor prices for various country/categories that are subject to quantitative restraints.

(ii) While fixing floor price, the average unit value realisation in the recent past, the trends in utilisation of levels and the fluctuation in exchange rate shall be taken into consideration.

13. Handloom Garments.—Special quantities reserved for handloom garments under the bilateral agreements for certain countries will be allotted under FCFS System.

14. Provisions regarding submission and forfeiture of Earnest Money Deposits|Bank Guarantees.—(i) In case of PPE, MEE and NQE systems, exporters will not be required to furnish EMD|BG during the original validity of the entitlement. However, unutilised quantities as on 30th September can be extended upto 31st December subject to EMD|BG @ 30 per cent (calculated on the basis of the applicable Floor Prices).

(ii) In case of FCFS system, an exporter shall be required to give EMD|BG @ 5 per cent of the FOB value on the quantities applied for.

(iii) Exporters who have entitlements of not less than 25,000 pcs for all categories taken together in any one of the systems of PPE or MEE or NQE will have an option of submitting a Legal Undertaking (LUT) in place of EMD|BG, subject to the following conditions :—

(a) The facility of submitting LUT in place of EMD|BG will apply to extension/revalidation of the entitlements of eligible exporters in PPE, NQE and MEE systems including PPT and NQT. In FCFS system, this facility will not be available for allotments.

(b) If DG, AEPC, raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter concerned who had submitted the Legal Undertaking would remit the amounts so claimed by DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim, failing which the exporter will not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of Entitlements or return of EMD|BGs in any systems until the amounts are remitted and DG, AEPC decides to reinstate these facilities for the exporter.

(c) DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD|BG for any exporters who are otherwise eligible for the facility, but have failed to remit any forfeiture amounts within the stipulated period of 90 days.

(d) The guidelines and stipulations applicable to EMD|BG will also apply to LUT, mutatis mutandis.

(iv) THE EMD|BG of an exporter who exports not less than 90% of the export entitlement shall be released in full. The DG, AEPC shall forfeit the EMD|BG in case utilisation is upto 75% in case of fast moving items and upto 50% in case of slow moving items, proportionate to the short-fall in utilisation. If utilisation of export entitlement allocation is less than the above percentages, EMD|BG shall be forfeited in full. For this purpose utilisation shall be computed on individual entitlements or on the basis of each system separately.

(v) If an exporter surrenders his entitlements under FCFS system either during the original validity period or within a period of 3 days of the expiry of the original validity, 50 per cent of the applicable amount in the EMD|BG or LUT will be released.

(vi) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a Public Deposit account of Government to be operated in such manner as Government decides from time to time.

(vii) All applications for extension shall be submitted complete in all respects before the expiry of the validity of the original entitlement or within a grace period of three working days from the date of expiry of the entitlement.

**15. Appeal against Forfeiture of EMD/BG/LUT.—**An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by DG, AEPC under para 13(iv) above may appeal before the Textile Commissioner, Bombay against such forfeiture within 60 days of despatch of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he will take into consideration the conditions of forfeiture spelt out in this notification, in addition to force majeure conditions. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officers as designated by him.

**16. Guidelines for obtaining release of held-up consignments.—**(a) Where a shipment effected in a non-quota category or in another restrained category is reclassified by the importing country into a restrained category, EC/Visas for the reclassified category should be issued after the exporter surrenders the necessary quota in any system other than FCFS. If FCFS balance is available for allotment, EC/Visas may be issued, without the exporter surrendering any quota, by debiting to such FCFS balance. The stipulations of this para will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected in FCFS System or in any of the other systems after obtaining extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required.

(b) Where a shipment exported in a restrained category is reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions :—

(i) The exporter returns the original EC/Visa that had been issued to him.

(ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export remains valid for the concerned quantity when the add-back is requested.

(c) In (a) above, the floor price of the reclassified category should be realised. This condition, however, may be relaxed by The Textile Commissioner in deserving cases.

(d) In the case of items exported as handloom garments exempted from restraints or as "India Items", which are reclassified by the importing countries as restrained items Visa/Export Certificates will be issued by DG, AEPC after obtaining the approval of the Ministry of Textiles.

(e) In cases where the exporter is required to surrender quotas for reclassified categories, he will be allowed to do so, from his own entitlements in PPE, NQE or MEE, or entitlements obtained by transfer. If the case is to be cleared after the 1st of October, when transfers are not permissible and the exporter does not have his own entitlements to surrender, he may furnish an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31st of January, from the succeeding years' (his own or transferred). Such an undertaking should be backed by EMD/BG to the extent of 50 per cent of the value of the quantity (calculated at the Floor Price Value).

Once the quantity is surrendered, the EMD/BG may be released. If the quantity is not surrendered as per the undertaking, the EMD/BG may be forfeited. In such cases, PP, NQ, ME allotments in any country/category to the exporter for the succeeding year may be allotted, only after the requisite quantity is surrendered.

**17. Procedure to deal with quota malpractices by exporters and Quota Agents :**

(i) Exporters who are found to have indulged in any fraudulent activity in connection with obtaining, utilising or proving the utilisation of quotas, may be issued show-cause Notices by DG, AEPC for explaining their conduct.

(ii) The cases shall be considered by a Committee with the following composition :

The Textile Commissioner	—Chairman
Director General AEPC	—Member
Chairman, AEPC	—Member
The three Vice Chairmen of AEPC	—Members

Senior Director/Director (QP), AEPC	—Member Secretary
-------------------------------------	-------------------

(iii) In cases where the Committee finds the exporter guilty of fraud after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.

(iv) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by DG, AEPC before personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.

(v) The Committee will be called the Enforcement Committee and for hearing appeals against the decisions of the Enforcement Committee, an Enforcement Appellate Committee is constituted with the following composition :

Joint Secretary (Exports), Ministry of Textiles	—Chairman
---	-----------

Additional/Joint Legal Advisor —Member  
Ministry of Law, Justice and  
Company Affairs as nominated by  
Law Secretary.

Export Commissioner —Member

Deputy Secretary (Exports) —Member  
Ministry of Textiles Secretary

(vi) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committee on appeal from the exporter or by calling for the details from DG, AEPC, on its own.

(vii) The provisions of this paragraph will apply, *mutatis mutandis*, to Quota Agents who are found to have indulged in any fraudulent activity relating to export entitlements.

### 18. Clearance by Customs :

(a) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA.—Shipments will be allowed by Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the DG, AEPC.

(b) Handloom Garments.—In so far as exports of all handloom garments except tailored collar Shirts corresponding to restrained items in Canada, Cotton handloom garments to Austria and special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories to USA, EEC, Norway and Finland, shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form, in addition to certification of shipping bills by DG, AEPC.

(c) Garments falling under India items : In respect of India items which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Norway, and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts), in addition to certification of shipping bills by DG, AEPC.

19. (a) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa : The following certificates required under the relevant Bilateral Textile Agreements will be issued by DG, AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :

1. EEC—(a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint.

(b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.

2. Finland.—Export Certificates for restrained items.

3. Austria.—Export Certificates for garments subject to restraint or surveillance.

4. Norway.—Export Certificates and Certificates of Origin in respect of categories subject to specific limits.

5. Canada.—Export Certificate for garments of knitted, powerloom and mill-made origin are subject to restraint except for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.

6. U.S.A.—Visa for all garment/knitwear consignments except properly marked samples valued at US \$ 250 or less.

(b) Handloom Certificate : In the case of export of all Handloom Garments, except Tailored Collar Shirts, corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Garments to Austria and special quantities reserved for Handloom Garments in some of the restrained categories to EEC, Norway, Austria and Finland the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

20. Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

21. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions as may be found necessary without giving prior notice. Government also reserves the right to amend the policy as necessary depending upon the outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of Multi Fibre Arrangement

22. The addresses of the Apparel Export Promotion Council and the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as following :—

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58 Nehru Place, New Delhi-110019.

2. Office of the Textile Commissioner, New CGO Complex, New Marine Lines, (Post Box No. 11500), Bombay-400020.

3. Textile Committee "Crystal" 79 Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.

4. Development Commissioner (Handicraft), West Block-VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.